::आयुक्त (अपील्स) का कार्यालय,वस्तु एवं सेवा करऔरकेन्द्रीय उत्पाद शुल्क::
O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), GST &CENTRAL EXCISE
द्वितीय तल,जी एस टी भवन / 2nd Floor, GST Bhavan
रेस कोर्स रिंग रोड / Race Course Ring Road
राजकोट / Rajkot – 360 001
Tele Fax No. 0281 – 2477952/2441142Email: commrappl3-cexamd@nic.in

सत्यमेव जयते

DIN20230264SX000000DD06

अपील / फाइलसंख्या/ Appeal /File No. **GAPPL/COM/STP/1452/2022**	मूल आदेश सं / O.I.O. No. **14/AC/NIS/BVR-3/22-23**	दिनांक/Date **06-04-2022**

क

अपील आदेश संख्या(Order-In-Appeal No.):

BHV-EXCUS-000-APP-022-2023

आदेश का दिनांक / Date of Order: **30.01.2023**	जारी करने की तारीख / Date of issue:**01.02.2023**

श्री शिव प्रताप सिंह, आयुक्त (अपील्स), राजकोट द्वारा पारित /

Passed by **Shri Shiv Pratap Singh**,Commissioner (Appeals),Rajkot.

ग अपर आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त/ सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर/वस्तु एवंसेवाकर,राजकोट / जामनगर / गांधीधाम। द्वारा उपरलिखित जारी मूल आदेश से सृजित: /
Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central Excise/ST / GST, Rajkot / Jamnagar / Gandhidham :

घ अपीलकर्ता&प्रतिवादी का नाम एवं पता /Name & Address of theAppellant&Respondent :-

M/s. Ravibhai Jagdishchandra Jani, Near Tatav Jyoti, Vavera Road, Rajula -365560Amreli, Gujrat

इस आदेश(अपील) से व्यथित कोई व्यक्ति निम्नलिखित तरीके में उपयुक्त प्राधिकारी / प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है।/
Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way.

(A) सीमा शुल्क ,केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम ,1944 की धारा 35B के अंतर्गत एवं वित अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अंतर्गत निम्नलिखित जगह की जा सकती है ।/

Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section 86 of the Finance Act, 1994 an appeal lies to:-

(i) वर्गीकरण मूल्यांकन से सम्बन्धित सभी मामले सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठ, वेस्ट ब्लॉक नं 2, आर. के. पुरम, नई दिल्ली, को की जानी चाहिए ।/

The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2, R.K. Puram, New Delhi in all matters relating to classification and valuation.

(ii) उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में बताए गए अपीलों के अलावा शेष सभी अपीलें सीमा शुल्क,केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट)की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका,,द्वितीय तल, बहुमाली भवन असार्वा अहमदाबाद- ३८००१६को की जानी चाहिए ।/

To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at, 2nd Floor, Bhaumali Bhawan, Asarwa Ahmedabad-380016in case of appeals other than as mentioned in para- 1(a) above

(iii) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील)नियमावली, 2001, के नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित किए गये प्रपत्र EA-3 को चार प्रतियों में दर्ज किया जाना चाहिए । इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की माँग ,ब्याज की माँग और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम,5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्टार के नाम से किसी भी सार्वजिनक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए । संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है । स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा ।/

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 / as prescribed under Rule 6 of Central Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against one which at least should be accompanied by a fee of Rs. 1,000/- Rs.5000/-, Rs.10,000/- where amount of dutydemand/interest/penalty/refund is upto 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asst. Registrar of branch of any nominated public sector bank of the place where the bench of any nominated public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated. Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-

B) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील, वित्त अधिनियम,1994 की धारा 86(1) के अंतर्गत सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(1) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-5 में चार प्रतियों में की जा सकेगी एवं उसके साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसकी प्रति साथ में संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां सेवाकर की माँग ,ब्याज की माँग और लगाया गया जुर्माना,रुपए 5 लाख या उससे कम,5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्टार के नाम से किसी भी सार्वजिनक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए । संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है । स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा ।/

The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994, to the Appellate Tribunal Shall be filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and Shall be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fees of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied of Rs. 5 Lakhs or less, Rs.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated. / Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs.500/-.

(i) वित्त अधिनियम,1994 की धारा 86 की उप-धाराओं (2) एवं (2A) के अंतर्गत दर्ज की गयी अपील, सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(2) एवं 9(2A) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-7 में की जा सकेगी एवं उसके साथ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा पारित आदेश की प्रतियाँ संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और आयुक्त द्वारा सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर, को अपीलीय न्यायाधिकरण को आवेदन दर्ज करने का निर्देश देने वाले आदेश की प्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी । /

The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filed in For ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) & 9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissionerauthorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise/ Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal.

(ii) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सेस्टेट) के प्रति अपीलों के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 35एफ के अंतर्गत, जो की वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, इस आदेश के प्रति अपीलीय प्राधिकरण में अपील करते समय उत्पाद शुल्क/सेवा कर मांग के 10 प्रतिशत (10%), जब मांग एवं जुर्माना विवादित है, या जुर्माना, जब केवल जुर्माना विवादित है, का भुगतान किया जाए, बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत जमा कि जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रुपए से अधिक न हो।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत "मांग किए गए शुल्क" में निम्न शामिल है

(i) धारा 11 डी के अंतर्गत रकम
(ii) सेनवेट जमा की ली गई गलत राशि
(iii) सेनवेट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम

- बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (सं. 2) अधिनियम 2014 के आरंभ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थगन अर्ज़ी एवं अपील को लागू नहीं होगे।/

For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 83 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores,

Under Central Excise and Service Tax, "Duty Demanded" shall include :

(i) amount determined under Section 11 D;
(ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
(iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules

- provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.

(C) **भारत सरकार कोपुनरीक्षण आवेदन :**
Revision application to Government of India:

इस आदेश की पुनरीक्षणयाचिका निम्नलिखित मामलो में, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम,1994 की धारा 35EE के प्रथमपरंतुक के अंतर्गतअवर सचिव, भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन ईकाई, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, को किया जाना चाहिए। /

A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35B ibid:

(i) यदि माल के किसी नुकसान के मामले में, जहां नुकसान किसी माल को किसी कारखाने से भंडार गृह के पारगमन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक भंडार गृह से दूसरे भंडार गृह पारगमन के दौरान, या किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में माल के नुकसान के मामले में।/

In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse

(ii) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर रहे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर भरी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छूट (रिबेट) के मामले में, जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की गयी है। /

In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.

(iii) यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भूटान को माल निर्यात किया गया है। /

In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.

(iv) सुनिश्चित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी क्रेडीट इस अधिनियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो आयुक्त (अपील) के द्वारा वित्त अधिनियम (न. 2),1998 की धारा 109 के द्वारा नियत की गई तारीख अथवा समायावधि पर या बाद में पारित किए गए है।/

Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

(v) उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियां प्रपत्र संख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील)नियमावली,2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, इस आदेश के संप्रेषण के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए । उपरोक्त आवेदन के साथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-EE के तहत निर्धारित शुल्क की अदायगी के साक्ष्य के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। /

The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

(vi) पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्नलिखित निर्धारित शुल्क की अदायगी की जानी चाहिए ।

जहाँ संलग्न रकम एक लाख रूपये या उससे कम हो तो रूपये 200/- का भुगतान किया जाए और यदि संलग्न रकम एक लाख रूपये से ज्यादा हो तो रूपये 1000 -/ का भुगतान किया जाए।

The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

(D) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशो का समावेश है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुल्क का भुगतान, उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिये। इस तथ्य के होते हुए भी की लिखा पढ़ी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय नयाधिकरण को एक अपील या केंद्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता हैं । / In case, if the order covers various umbers of order- in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each.

(E) यथासंशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975, के अनुसूची-I के अनुसार मूल आदेश एवं स्थगन आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का न्यायालय शुल्क टिकिट लगा होना चाहिए। /

One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act,1975, as amended.

(F) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्य विधि) नियमावली, 1982 में वर्णित एवं अन्य संबन्धित मामलों को सम्मिलित करने वाले नियमों की और भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। /

Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

(G) उच्च अपीलीय प्राधिकारी को अपील दाखिल करने से संबंधित व्यापक, विस्तृत और नवीनतम प्रावधानों के लिए, अपीलार्थी विभागीय वेबसाइट www.cbec.gov.in को देख सकते हैं । /

For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website www.cbec.gov.in.

:: अपील आदेश / ORDER-IN-APPEAL ::

M/s. Ravibhai Jagdishchandra Jani, Rajula (hereinafter referred to as "Appellant") has filed the present Appeal against Order-in-Original No. 14/AC/NIS/BVR-3/22-23 dated 06.04.2022 (hereinafter referred to as 'impugned order') passed by the Assistant Commissioner, Central GST Division-3, Bhavnagar (hereinafter referred to as 'adjudicating authority').

2. The facts of the case, in brief, are that the Income Tax Department shared the third-party information/ data based on Income Tax Returns/ 26AS for the Financial year 2014-15, 2015-16 & 2016-17 of the Appellant. Letter dated 22.07.2020 was issued by the Jurisdictional Range Superintendent requesting the Appellant to provide information/documents viz. copies of I.T. Returns, Form 26AS, Balance Sheet (including P&L Account), VAT/ Sales Tax Returns, Annual Bank Statement, Contracts/ Agreements entered with the persons to whom services provided etc. for the Financial year 2014-15, 2015-16 & 2016-17. However, no reply was received from the Appellant.

3. In absence of data/ information, a Show Cause Notice dated 27.08.2020 was issued to the Appellant, demanding Service Tax and cess to the tune of Rs. 4,42,434/- under Section 73(1) of the Finance Act, 1994 (hereinafter referred to as 'the Act') alongwith interest under Section 75 of the Act. It was also proposed to impose penalties under Section 77(1)(a), 78, 77(2) and 77(1)(c) of the Act upon the Appellant.

4. The adjudicating authority vide the impugned order confirmed the demand of Rs. 4,42,434/- under Section 73(1) along with interest under Section 75 of the Act, imposed penalty of Rs. 4,42,434/- under Section 78 of the Act, imposed penalty of Rs. 5,000/- each under Section 77(1)(a), 77(2) and 77(1)(c) of the Act.

5. Being aggrieved, the Appellant has preferred the present appeal on various grounds that the Adjudicating Authority wrongly confirmed the demand, interest and wrongly imposed various penalties.

6. The matter was posted for hearing on 25.01.2023. CA Abhishek P Doshi appeared for personal hearing and handed over paper-book with written submissions and supporting documents. He reiterated the submissions and those in the appeal. He submitted that after deducting sale of materials from the total receipts, service turnover was below threshold limit in each of the 3 years. In this regard appellant has provided all documents such as Balance Sheet, Profit & Loss account, invoices etc. Therefore, he requested to set aside the Order-In-Original.

7. The CA on behalf of the Appellant handed over paper-book wherein it has

been stated that they are proprietorship firm engaged in mining quarry supporting service and sale of blasting material. The Show Cause Notice was issued on 27.08.2020 for the period 2014-15 to 2016-17 on the ground that gross income mentioned in the income tax return is more than 10 Lakhs. They submitted reply to Adjudicating Authority vide their letter dated 24.02.2022 which was not considered by the Adjudicating Authority. They were not required to obtain Service Tax registration as the aggregate value of taxable services does not exceed Rs. 10 lakhs in any financial year. Their turn over also includes value of sale of materials. In income tax return they have mistakenly shown entire receipts in turnover of services instead of turnover of goods and turnover of services. The disclosure in income tax return cannot be determined nature of activities. In support, they have submitted copy of Profit & Loss account and copy of invoices for sale of material in all 3 years evidencing that there was sale of material. After deducting value of sale of materials, the turnover of services during the financial year 2014-15 to 2016-17 come down under Rs. 10 Lakhs. They also submitted copy of Profit & Loss for the year 2013-14 in which total income was Rs. 5,46,040/-.

6.2 The Show Cause Notice based on ITR/26As is not valid as the same has been issued in usual course of charges only related to appellant's information and with nothing more emphasized on the nature of activity to be classified under a particular service. They rely on CESTAT Delhi judgment in the case of Deltax Enterprises Vs. CCE, Delhi - 2018 (10) GSTL 392 (Tri.-Del), Faquir Chand Gulati Vs. Uppal Agencies Pvt. Ltd. - 2008 (12) STR 401 (S.C.), Krishna Construction Co. Vs. CCE & S.T. Bhavnagar, Final Order No. A/10973/2022 CESTAT- Ahmedabad, Kush Constructions Vs. CGST Nacin, 2019 (24) GSTL 606 (Tri.-All), Luit Developers (P) Ltd. Vs. Commissioner of CGST & Central Excise Dibrugarh - 2022 (136) taxmann.com 109 (Kolkata-Cestat).

6.3 The Larger period cannot be invoked since the Show Cause Notice is based on ITR/Form 26AS which is available with the Government and hence the allegation of suppression cannot be made and they placed reliance on decision in the case of Pappu Crane Service Vs. Commissioner of Service Tax Appeal No. 70707 of 2018-DB, Luit Developers (P) Ltd. Vs. Commissioner of CGST & Central Excise Dibrugarh - 2022 (136) taxmann.com 109 (Kolkata-Cestat). The Show Cause Notice does not have any evidence to show that the Appellant suppressed any information with an intention to evade payment of Service Tax. The Show Cause Notice dated 21.12.2020 for the period 2014-15 to 2016-17 is barred by limitation as period of 5 years for 2014-15 was over by March-2020. The Adjudicating Authority has wrongly charged interest and imposed penalties. They relied on the case of Hindustan Steel Ltd. Vs. State of Orissa - 2002-TIOL-148-SC-

CT-LB and Commissioner of Service Tax Vs. Motorworld and others- 2012-TIOL-418-HC-KAR-ST.

7. I have carefully gone through the case records, impugned order and appeal memorandum filed by the Appellant. I find that Show Cause Notice had been issued without verifying any data or nature of services provided by the Appellant as the same had been issued only on the basis of data received from the Income Tax department. The Adjudicating Authority has confirmed the demand of Service Tax vide impugned order after considering the reply filed by the Appellant.

8. I find that the main issue that is to be decided in the instant case is whether the activity carried out by the Appellant is covered under exemption and as to whether the amount received for providing the services is taxable, or otherwise.

9. On verification of profit & loss account for the year 2014-15, 2015-16 & 2016-17, it is seen that which Service Tax has been demanded on total income. However, this total income comprise of (i) contract work income and (ii) material sales during the period under dispute. The Appellant produced sample copies of invoices wherein they have sold blasting materials to varous parties/ customers. The same is being reflected in the books of account maintained by the Appellant. It is on record that after deducting value of sale of materials i.e. blasting materials, the taxable value come down below Rs. 10 Lakh in all financial year 2014-15 to 2016-17. It is admitted fact the trading is falling under negative list and no Service Tax can be demanded on trading activities.

10. I find that the term 'service' is defined under Section 65(44) of the Act as under:

> *"Service means any activity carried out by a person for another for consideration, and includes a declared service, but shall not include-*
>
> *(a) An activity which constitute merely-*
>
> *(i) A transfer of title in goods or immovable property, by way of sale, gift or in any other manner; or*
>
> *(ii)....*
>
> *(iii) ...."*

Under Section 66B of the Act, service tax shall be levied on the value of all services, other than those service specified in the negative list. Negative list denotes the list of services on which no service tax is payable under Section 66B of the Act. As per Section 66D (e), trading of goods is a service specified under the negative list which is as under:

> *"SECTION 66D. Negative list of services.—*
>
> *The negative list shall comprise of the following services, namely :—*

(a)....

(b) ....

(c) ....

(d)....

(e) trading of goods;"

Accordingly, on the activity of trading of goods, no service tax is payable.

10.1 Section 66B provides that service tax is leviable on all 'services' other than the services specified under the negative list. Therefore, for being subject to service tax an activity needs to qualify as a service first. The term 'service' is defined under Section 65B (44) which specifically excludes an activity of mere transfer of title in goods by way of sale. Thus, the activity of trading which is merely buying and selling of the goods is not a service. Hence, the question of service tax levy on the same does not arise. Accordingly, it is not liable to service tax, as the same is not a service. Further, negative list of services comprises services but an activity of trading of goods is not a service, therefore it can be specified under the negative list of services.

11. After considering sale of materials out of total taxable value, the net taxable value of services comes to Rs. 9,10,909/-, Rs. 7,78,213/- and Rs. 8,42,200/- for the financial year 2014-15, 2015-16 & 2016-17 which is below threshold limit of Rs. 10 Lakh as envisaged under Notification No. 33/2012-Service Tax dated 20.06.2012. Therefore, I am of considered view that the Appellant is not liable to pay Service Tax on the value of taxable service which is below Rs. 10 Lakhs.

12. In view of discussions and finding, I set aside the impugned order and allow the appeal filed by the Appellant.

13. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है ।

13. The appeal filed by Appellant is disposed off as above.

सत्यापित / Attested

28-01-2023

(शिव प्रताप सिंह)/(Shiv Pratap Singh),

आयुक्त (अपील)/Commissioner (Appeals)

Superintendent
Central GST (Appeals)
Rajkot

By R.P.A.D.

To, M/s. Ravibhai Jagdishchandra Jani, Near Tatav Jyoti, Vavera Road, Rajula-365560, Dist.: Amreli, Gujarat	सेवा में, मे. रविभाई जगदीशचंद्र जानी, टाटाव ज्योति के पास, वावेरा रोड, राजुला-365560, जिल्ला: अमरेली, गुजरात ।

प्रतिलिपि :-

1) मुख्य आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गुजरात क्षेत्र, अहमदाबाद

को जानकारी हेतु।

2) आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, भावनगर आयुक्तालय, भावनगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3) अपर आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, भावनगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4) सहायक आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मण्डल-3, भावनगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5) गार्ड फ़ाइल।